सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक - आ॰ का/85/19
दिनांक - 06/09/2019.

प्रिय रघुवर जी,

आज के अखबारों में पढ़ा कि जिस स्थान पर 465 करोड़ रूपये के खर्च पर बने विधानसभा भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलो से होने वाला है, उसके ठीक सामने 1258 करोड़ रूपये के खर्च पर झारखण्ड सरकार का नया सचिवालय बनेगा जिसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी जायेगी।

राज्य की नाजुक वित्तीय स्थिति से आप भली–भांति अवगत हैं। विभिन्न कार्य विभागों में 5,000 करोड़ रूपये से अधिक के बिल पेंडिंग हैं। संपन्न हो चुके कार्यों के एवज में करीब 13,000 करोड़ रूपया पी.एल. खाता में संधारित है। वार्षिक योजना बजट में कटौती करनी पड़ रही है। मार्च 2019 में पूरा हुये वित्तीय वर्ष (2018–19) का योजना व्यय बजट 44,000 करोड़ रूपया निर्धारित था। वित्तीय संसाधन नहीं जुट पाने के कारण इसे घटाकर 36,000 करोड़ रूपया करना पड़ा। इसमें से भी करीब 10,000 करोड़ रूपया पी.एल. खाता में जमा कर देना पड़ा। यानी इस वर्ष राज्य का योजना व्यय वस्तुतः मात्र 26 हजार करोड़ रूपया पर सिमट कर रह गया। एक ओर राज्य योजना के लिए वित्तीय संसाधन का अभाव परिलक्षित हो रहा है और कई जरूरी घोषणायें पूरा करने के लिए सरकार को बाजार से लिये गये भारी कर्ज का उपयोग करना पड़ रहा है तो दूसरी ओर सरकार सचिवालय बनाने जैसे अनुपयोगी कार्य पर 1258 करोड़ रूपये खर्च करने जा रही है। ऐसी स्थिति में ऐसा करना उचित नहीं प्रतीत हो रहा है, यह व्यय अपव्यय कहा जायेगा और इसकी गिनती फिजुलखर्ची की श्रेणी में होगी।

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार के सचिवालय और निदेशालयों का कार्य संपन्न करने के लिए प्रोजेक्ट भवन, एम.डी.आई. बिल्डिंग, नेपाल हाउस, हाल में बना विकास भवन, धुर्वा गोलचक्कर पर एवं अन्यत्र उपलब्ध कई अन्य भवनों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। कम से कम अगले 15–20 वर्षों के लिए सचिवालय एवं निदेशालयों के काम के लिए ये स्थान पर्याप्त हैं और इसके लिए किसी अतिरिक्त भवन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति में 1258 करोड़ रूपया खर्च कर नया सचिवालय निर्माण करने का कोई तुक प्रतीत नहीं हो रहा है।

सचिवालय निर्माण पर किये जाने वाले 1258 करोड़ रूपये के व्यय से राज्य के विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी अस्पतालों, जल–संचय योजनाओं, शहरी गरीबों की योजनायें,

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651–2401023, फैक्स : 0651–2482455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

सिंचाई, कृषि एवं ग्रामीण विकास की संरचनाओं का निर्माण किया जाय एवं पहले बनी संरचनाओं की मरम्मत/उन्नयन इस निधि से कर दिया जाय तो राज्य को और राज्य की जनता को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इससे राज्य की वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और जनता का जीवन स्तर उपर उठाने में मदद मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि इसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी साहेबगंज में बनाये गये पोर्ट–टर्मिनल का उद्घाटन भी करने वाले हैं जिसे बनाने में मात्र 300 करोड़ रूपये खर्च हुआ हैं। परन्तु इसके बनने से झारखण्ड एवं बिहार के बड़े इलाकों को और इन इलाकों की जनता को सीधा आर्थिक लाभ पहुँचेगा। कालक्रम में यह लाभ नेपाल और पूर्वोतर राज्यों तक पसर जायेगा। परन्तु झारखण्ड सरकार के सचिवालय पर 1258 करोड़ रूपया खर्च कर देने से राज्य और राज्य की जनता को कोई तात्कालिक अथवा दीर्घकालिक लाभ नहीं पहुँचेगा। यह व्यय अनावश्यक व्यय कहा जायेगा।

अनुरोध है कि झारखण्ड सरकार के लिये नया सचिवालय निर्माण की इस परियोजना को राज्यहित एवं जनहित मे फिलहाल स्थगित रखा जाय।

सरयू,

सरयू राय

सेवा में,
श्री रघुवर दास
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखण्ड सरकार।

प्रतिलिपि – 1. सभी माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार ।

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner